

हिण्डौन सिटी, शनिवार 23 सितम्बर, 2023

30 सितम्बर तक फिर से 5% रेट बढ़ेगी

FIXED
PRICENO MIDDLE-MEN
DIRECT TO
CUSTOMER

KEDIA
सेजस्थान
KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड, जयपुर

2 साइड ओपन कोठी और फ्लैट्स | 60 एमेनिटीज



PROPOSED FIXED RATE & RENTAL 1.5 लाख

बड़ी-बड़ी कोठी बड़े-बड़े फ्लैट	अगस्त की रेट	सितम्बर की रेट	अक्टूबर की रेट	नवम्बर की रेट	दिसम्बर की रेट	जनवरी की रेट	पजेशन की रेट	
युनिट टाइप	N.P.O. NEW PRODUCT OFFER	5% +	10% +	15% +	20% +	25% +	50% +	POSSESSION DEC. 2025
2 BHK (GF) अपार्टमेंट	45 L	47.25 L	49.50 L	51.75 L	54 L	56.25 L	67.50 L	22,000
3 BHK (SF) अपार्टमेंट	50 L	52.50 L	55 L	57.5 L	60 L	62.50 L	75 L	25,000
3 BHK (FF) अपार्टमेंट	55 L	57.75 L	60.5 L	63.25 L	66 L	68.75 L	82.50 L	28,000
3 BHK BIG कोठी	60 L	63.00 L	66 L	69 L	72 L	75 L	90 L	30,000
4 BHK BIGGER कोठी	70 L	73.50 L	77 L	80.50 L	84 L	87.50 L	105 L	40,000
4 BHK BIGGEST कोठी	100 L	105 L	110 L	115 L	120 L	125 L	150 L	50,000

OKEDIA®

1800-120-2323

info@kedia.com www.kedia.com

www.rera.rajasthan.gov.in | RERA No. RAJ/P/2023/2387

WALKTHROUGH
QR CODEDOWNLOAD
BROCHURELOCATION
QR CODEROUTE
MAPSITE TOUR
360 DEGREE

*T&C Apply

विचार बिन्दु

निरंतर विकास जीवन का एक नियम है। और जो भी व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए अपनी रुढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वो खुद को एक गलत स्थिति में पहुंचा देता है। -महात्मा गांधी

तेरे द्वार खड़ी सरकार भक्त भर दे रे तिजोरी

स

भी जनते हैं कि सरकार की साप्ताहिक प्रशासन व्यवस्था जनता के द्वारा दिया गया (अब नहीं, लिए गए) टेक्स से चर्चा है। भले ही आपके बोट द्वारा तथाकथित उन्हें हुए प्रवादिक और संसद जब सदन में बैठते हैं तो वह सरकार के हिस्से हो जाते हैं चाहे पक्ष में हो अथवा विषय में पक्ष में बैठते हैं तो सरकार की हाँ में हाँ और विषय में होने पर चुपचाप वाद-विवाद सुनना या हुल्लड मचाना। चुप रहने पर भी लगता ऐसा है कि सरकार के पक्ष में है। इस स्थिति का लाभ सरकार उड़ाता है (पर्याप्त हित) के प्रस्ताव पास कर लेता है। मूल बाटने के पक्ष में है। इस स्थिति का लाभ सरकार के पक्ष में है। जब सरकार कोई बैक्स वृद्धि करना चाहता है अथवा लुटे-पिटे अपने लोगों को कुछ मुफ्त देने का प्रयास करता है, तभी ही आम जनता के लिए ऐसे प्रस्ताव अहितक होता। कारण साफ है कि जब जनता चिल्लायेंगी तो विषय को उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। इसलिए जनता के अहितकर कुछ मुद्दों पर सत्य में अधिक विरोध नहीं होता।

अभी इसी असंबोल के सितंबर 13 के अक में श्री सी ए शंकर अग्रवाल द्वारा बहुत सूनर सम्पादकीय लिखा है शीर्षक है "सब कुछ मुफ्त बांने की प्रति के कारण राजस्थान सरकार का बदला करता है" लेख का विषय सामानी और विवेक अंथर्योगी और साहसीनी है। यहाँ एक लेखक की व्याख्या साफ़ दिखती है। लेकिन राजस्थान की प्रजा से जैसा चाहित है, वे न तो लेख पढ़ते और न ही कोई विरोध। इसलिए अनेक मुद्दों पर न तो उनकी कोई सोच होती है और न ही कोई प्रतिक्रिया। उत्तर लेखक ने कुछ वर्षों का प्रदेश पर बढ़ावा लगाया है। लगातार बढ़ते छप्पन से प्रदेश पर वर्ष 2022-23 में 53,701 कोरड़ रुपये अंतर्यामी लाख सौंतीस हजार कोरड़ का कांगे गए थे या नहीं? अब वह सरकार को इस बढ़ते छप्पन से कोई वित्ती विधि के लिए चुकाए गए थे या नहीं? अपनों को लाए औंचुल (दोनों हाथ की मिला कर हथेलियां) भर भर देते हैं। इसकी चुकाने की तरह कोई चिंता नहीं रहती। छप्पन के वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है। साधार उड़ाने मान लिया है, कि दूसरी सरकार चुकायेगी। और यदि आपावधि खुद ही चुकाना पड़ा तो अनेक रसोई है। विषय में टैक्स बढ़ाने और लगाने के, किसने देखा है? फिलहाल तो कोई न किलकान चाहिए।

प्रजा के अंदे रहने, गंगे नदी, मूक रहने और दिमागी दिवालिएन से किसी आम नागरिक में सामर्थ नहीं कि वह अनेक कुछ साधारियों से मिल कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सुप्रीमकोर्ट सीनियर अधिकारी श्री अश्वनी जी की भान्ति याचिकाओं के द्वारा लगा दें, कोर्ट की प्रार्थना करने कि सरकारी धन का मुफ्तहारी में व्यवहार काया औंडिटर जनरल औफ़ इंडिया को गुहार लाए कि मुफ्त का सारकारी व्यवसाय अवैधानिक धोखा हो। किसी भी ऐसे सरकारी धन के खर्च को बसलने की यांदेयारी व्यक्तिशः ऑफिटर जनरल की जाया।

प्रधान मंत्री को यह ब्राह्मचार प्रतीत नहीं होता क्या? जो कभी सामान्य बजट में पास नहीं किया जाता। इस प्रकार यह धंधा राजकीय खाने पर डाका है। यह बात एक बहुत बिरुद्ध वृत्ति की विषय है। मेरा तो अब सुझाव है कि सभी प्रादेशिक और केंद्रीय बजट (रक्षा बजट को छोड़ा) के लिए वित्ती विधि के लिए चुकाए गए थे या नहीं? अब वह सरकार को इस बढ़ते छप्पन से कोई चिंता नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े दानी हैं। अपनों को लाए औंचुल (दोनों हाथ की मिला कर हथेलियां) भर भर देते हैं। इसकी चुकाने की तरह कोई चिंता नहीं रहती। छप्पन के वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है। साधार उड़ाने मान लिया है, कि दूसरी सरकार चुकायेगी। और यदि आपावधि खुद ही चुकाना पड़ा तो अनेक रसोई है। विषय में टैक्स बढ़ाने और लगाने के, किसने देखा है?

भी प्रकार की सिस्टिक्सी जैसे रसोई गैस राशन, आदि पर बंद हो। सभी प्रकार के आरक्षण संविधान में बदलाव कर निरस्त किये जायें। पांच पीढ़ियां निकल जाने के पश्चात् भी पीछड़े, गरीब व् अन्य सरीखे यदि सामान्य वर्ग के बाबाबर नहीं आ पाए, तो इसके लिए आम जनता चिरकाल तक उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती, उसे क्यों प्रताङ्गित किया जा रहा है?

देश की प्रतिभाओं की तो पूर्व की सभी केंद्रीय सरकारों ने हत्या कर दी और अभी भी कर रही है। जागरूक जनता की आँख तो तब खुली है रुद्ध के समय हजारों भारतीय विद्यार्थी उड़ेन से सरकारी हस्तक्षेप से भारत लाये जा सकते। सप्ताह प्रदेश और केंद्र के विषय सारिंग और बड़े बड़े एवं बड़े अधिकारी एवं बड़े अधिकारी व्यवसाय अवैधानिक धोखा हो। किसी भी ऐसे सरकारी धन के खर्च को बसलने की यांदेयारी व्यक्तिशः ऑफिटर जनरल की जाया।

सभी प्रकार की यह ब्राह्मचार प्रतीत नहीं होता क्या? जो कभी सामान्य बजट में पास नहीं किया जाता। इस प्रकार यह धंधा राजकीय खाने पर डाका है। यह बात एक बहुत बिरुद्ध वृत्ति की विषय है। मेरा तो अब सुझाव है कि सभी प्रादेशिक और केंद्रीय बजट (रक्षा बजट को छोड़ा) के लिए वित्ती विधि के लिए चुकाए गए थे या नहीं? अब वह सरकार को इस बढ़ते छप्पन से कोई चिंता नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े दानी हैं। अपनों को लाए औंचुल (दोनों हाथ की मिला कर हथेलियां) भर भर देते हैं। इसकी चुकाने की तरह कोई चिंता नहीं रहती। छप्पन के वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है। साधार उड़ाने मान लिया है, कि दूसरी सरकार चुकायेगी। और यदि आपावधि खुद ही चुकाना पड़ा तो अनेक रसोई है। विषय में टैक्स बढ़ाने और लगाने के, किसने देखा है?

देश की प्रतिभाओं की तो पूर्व की सभी केंद्रीय सरकारों ने हत्या कर दी और अभी भी कर रही है। जागरूक जनता की आँख तो तब खुली है रुद्ध के समय हजारों भारतीय विद्यार्थी उड़ेन से सरकारी हस्तक्षेप से भारत लाये जा सकते। सप्ताह प्रदेश और केंद्र के विषय सारिंग और बड़े बड़े एवं बड़े अधिकारी एवं बड़े अधिकारी व्यवसाय अवैधानिक धोखा हो। किसी भी ऐसे सरकारी धन के खर्च को बसलने की यांदेयारी व्यक्तिशः ऑफिटर जनरल की जाया।

सभी प्रकार की यह ब्राह्मचार प्रतीत नहीं होता क्या? जो कभी सामान्य बजट में पास नहीं किया जाता। इस प्रकार यह धंधा राजकीय खाने पर डाका है। यह बात एक बहुत बिरुद्ध वृत्ति की विषय है। मेरा तो अब सुझाव है कि सभी प्रादेशिक और केंद्रीय बजट (रक्षा बजट को छोड़ा) के लिए वित्ती विधि के लिए चुकाए गए थे या नहीं? अब वह सरकार को इस बढ़ते छप्पन से कोई चिंता नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े दानी हैं। अपनों को लाए औंचुल (दोनों हाथ की मिला कर हथेलियां) भर भर देते हैं। इसकी चुकाने की तरह कोई चिंता नहीं रहती। छप्पन के वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है। साधार उड़ाने मान लिया है, कि दूसरी सरकार चुकायेगी। और यदि आपावधि खुद ही चुकाना पड़ा तो अनेक रसोई है। विषय में टैक्स बढ़ाने और लगाने के, किसने देखा है?

देश की प्रतिभाओं की तो पूर्व की सभी केंद्रीय सरकारों ने हत्या कर दी और अभी भी कर रही है। जागरूक जनता की आँख तो तब खुली है रुद्ध के समय हजारों भारतीय विद्यार्थी उड़ेन से सरकारी हस्तक्षेप से भारत लाये जा सकते। सप्ताह प्रदेश और केंद्र के विषय सारिंग और बड़े बड़े एवं बड़े अधिकारी एवं बड़े अधिकारी व्यवसाय अवैधानिक धोखा हो। किसी भी ऐसे सरकारी धन के खर्च को बसलने की यांदेयारी व्यक्तिशः ऑफिटर जनरल की जाया।

सभी प्रकार की यह ब्राह्मचार प्रतीत नहीं होता क्या? जो कभी सामान्य बजट में पास नहीं किया जाता। इस प्रकार यह धंधा राजकीय खाने पर डाका है। यह बात एक बहुत बिरुद्ध वृत्ति की विषय है। मेरा तो अब सुझाव है कि सभी प्रादेशिक और केंद्रीय बजट (रक्षा बजट को छोड़ा) के लिए वित्ती विधि के लिए चुकाए गए थे या नहीं? अब वह सरकार को इस बढ़ते छप्पन से कोई चिंता नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े दानी हैं। अपनों को लाए औंचुल (दोनों हाथ की मिला कर हथेलियां) भर भर देते हैं। इसकी चुकाने की तरह कोई चिंता नहीं रहती। छप्पन के वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है। साधार उड़ाने मान लिया है, कि दूसरी सरकार चुकायेगी। और यदि आपावधि खुद ही चुकाना पड़ा तो अनेक रसोई है। विषय में टैक्स बढ़ाने और लगाने के, किसने देखा है?

देश की प्रतिभाओं की तो पूर्व की सभी केंद्रीय सरकारों ने हत्या कर दी और अभी भी कर रही है। जागरूक जनता की आँख तो तब खुली है रुद्ध के समय हजारों भारतीय विद्यार्थी उड़ेन से सरकारी हस्तक्षेप से भारत लाये जा सकते। सप्ताह प्रदेश और केंद्र के विषय सारिंग और बड़े बड़े एवं बड़े अधिकारी एवं बड़े अधिकारी व्यवसाय अवैधानिक धोखा हो। किसी भी ऐसे सरकारी धन के खर्च को बसलने की यांदेयारी व्यक्तिशः ऑफिटर जनरल की जाया।

सभी प्रकार की यह ब्राह्मचार प्रतीत नहीं होता क्या? जो कभी सामान्य बजट में पास नहीं किया जाता। इस प्रकार यह धंधा राजकीय खाने पर डाका है। यह बात एक बहुत बिरुद्ध वृत्ति की विषय है। मेरा तो अब सुझाव है कि सभी प्रादेशिक और केंद्रीय बजट (रक्षा बजट को छोड़ा) के लिए वित्ती विधि के लिए चुकाए गए थे या नहीं? अब वह सरकार को इस बढ़ते छप्पन से कोई चिंता नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े दानी हैं। अपनों को लाए औंचुल (दोनों हाथ की मिला कर हथेलियां) भर भर देते हैं। इसकी चुकाने की तरह कोई च

ਮੈਂ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾ
ਜਨਨ ਕੀ ਬ੍ਰਾਤਾਂ
ਜਨਨ ਕੀ ਬ੍ਰਾਤਾਂ

त्योहार का जश्न मनावं बांड-दू कार पर, रमेशल औफर्स के साथ.



ALTO K10	S-PRESSO	SWIFT	WAGONR	CELERIO	EECO	₹34 000*
₹62 000*	₹71 000*	₹52 000*	₹51 000*	₹66 000*	₹60 000*	₹34 000*



hook today at www.maritidisuzuki.com or visit your nearest Mariti Suzuki dealership.

दृष्टि इंडियन सिटी, 23 सितम्बर, 2023

Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. It is inclusive of Contingent Terms and conditions available at Maruti Suzuki Arena authorized dealer. Maruti Suzuki Arena authorized dealer. Black glass on the vehicle is due to lighting effect. Images used are for illustration purpose only. *All loans and schemes are at the sole discretion of the Finance Partner.